ہے کہ اس طرح سے اشیو نہیں دے جائینگے تو بڑی مشکل ہو جائیگی۔]

उपसभापतिः मुझे मालूम नहीं है। मैं इसके बारे में मालूम करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी।

RE. ALLOTMENT OF STALLS TO PEPSI AT NEW DELHI RAILWAY STATION IN PREFERENCE TO A PUBLIC SECTOR UNIT

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, I want to raise an important issue. I am happy that some time back, our Industry Minister, Shri Karunakaranji, made a statement and reiterated that Government would not allow any public sector unit to be privatised and wherever sick units were there, he would make all efforts to revive them. I am very happy about it. We should take action on that line. *Interruptions.)*

SHRI M.A. BABY (Kerala): Words are very good. What about deeds?

The Vice-Chairman (Shri Suresh Pachouri) In the Chair.

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Vice-Chairman, we want the food-processing industry to be given more fillip, more advantage and more encouragement. But what happened? The Minister for Food-Processing Industries, Mr. Tarun Gogoi, wrote a letter to the Railway Minister. I am reading out from that letter. "I wish to take this opportunity to introduce the Modern Food Industries Limited, a Government of India Undertaking." That means, a public sector undertaking. "They should be allowed a stall on platform No. 10 for mango juice which they are giving by vending machines." It costs only Rs. 3/-. Unfortunately, after the letter was written by the Minister, on 21st September, 1994, the Private Secretary to the Minister of Railways wrote back stating that it was being looked into. A second reminder was sent. *(Interruptions).*

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): The reply was sent by the Private Secretary?

SHRI JAGESH DESAI: Yes. It was sent by the Private Secretary. I am sorry to report that instead of giving a stall to the public sector food-processing unit, three stalls were given, not one, on platform No. 10 in the New Delhi Railway Station, to the Pepsi Company. It was not given to our public sector company. How did it happen? I was always taking this juice because it would cost only Rs. 3/- per glass whereas Pepsi would cost Rs. 6/- or Rs. 7/- a glass. When I enquired, "Why should you not have a mango juice stall there?" I told them, "The Rajdhani Express leaves from platform No. 10. Why don't you have a stall on platform No. 10? In reply to that, it was said that they had already written in 1994. The public sector undertaking was not given any stall. And three stalls have been given to multinationals! Are we going to have multinationals or are we going to have public sector units? The sickness of our public sector is because of such reasons. If you want the public sector is to thrive, at least one stall should have been given to them. Let people take what they want, whether mango juice or Pepsi. Let it be left to them. Unfortunately, orders are not being received by the public sector units and many public sector units are becoming sick because they are not getting the orders. This was a small thing and even the Minister had written about it. I made enquiries with the Minister's office and I was given to understand that an enquiry has been made. But those who are sitting in the Baroda House have not cared even to furnish the enquiry report to the minister. If the report had been submitted to the Railway Minister, I am sure, the Railway Minister definitely would have

given it to the public sector. But, unfortunately, those who are sitting in the Baroda House, are not doing it. I would like the Minister to explain to us as to how it happened. I would also request him to make an enquiry and find out whether any illegal things were done because the public sector did not give any money. Others might have given. That is why I condemn it and I want an enquiry to be made into this matter.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही प्रतिष्ठित माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। अगर्चे उन्होंने प्लेटफार्म पर तीन स्टाल्ज़ के बारे में सवाल उठाया है लेकिन हमको लगता है कि जब मुल्क ही दिया जा रहा है मल्टीनेशनलज़ को, प्लेटफार्म का हम लोग क्या करें? लेकिन फिर भी मैं एक बात जानना चाहता हूं, वह यह है कि विपक्ष में और सरकारी पार्टी में ...(**व्यवधान**)

All right. Mr. Finance Minister, I am telling you.

SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA (Uttar Pradesh): He belongs to the CPI and not to the CPI(M).

SHRI CHATURANAN MISHRA: I am telling you that there is a difference between Jyoti Basu and you and the basic difference is that perhaps there are no two opinions about the multinational coming in certain sectors. But, in respect of food, drinks and consumer goods, we do not want them. This is the difference between you and Jyoti Basu because you have raised it.

मैं आपसे कहना चाहता था कि शासक पार्टी का इतिहास है देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का और उस शासक पार्टी के बारे में धारणा हो रही है कि मुल्क को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में बेच रहे हैं। क्यों आप फूड एंड ड्रिंक्स में भी सती होना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ पर, हम को समझ में नहीं आ रहा है। जब विपक्ष भी आपका साथ दे रहा है सर्टेन सेक्टर्ज़ में जहां जरूरी है, हम जाएं। लेकिन ख्वामखाह आप सती होने के लिए क्यों जा रहे हैं जिसको लार्ड विलियम बैंटिक ने गैर कानूनी कर दिया था। उसको आप फिर रिवाइव क्यों कर रहे हैं यह मुझे आपसे प्रश्न पूछना है?

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं जागेश देसाई जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की परंपरा को याद करते हुए अपनी बात को सही ढंग से रखने की कोशिश की और मनमोहन सिंह जी अगर आप अभी भी उनकी बात समझ लें तो देश में बहुत बुरी हालत होने वाली नहीं है (**व्यवधान**)

SHRI JAGESH DESAI: This is not a question of policy. This is a question of encouraging the public sector.

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले पूरे सदन ने सर्वसम्मति से अपनी राय ज़ाहिर की थी और मारग्रेट आल्वा जी यहां बैठी हुई थी। उन्होंने कहा था कि सदन की इस भावना से सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। इन्हीं सवालों से जुड़ा हुआ सवाल था कि इस देश में जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से खाने-पीने का समान बुलाया जा रहा है

केंटेकी फ्राइड चिकन से ले कर पेप्सी के जूस तक। इन सारी चीज़ों को इस देश में आने से रोका जाए। सारे सदन ने, चाहे किसी भी दल के लोग हों, सभी ने इसका समर्थन किया था। आज तक सरकार की तरफ से आपने प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश दिया, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिली है। मारग्रेट आल्वा जी ने सरकार की तरफ से यहां पर आश्वासन दिया था। यह रिकार्ड में है और सारे लोग जानते हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि सरकार सचमुच में उसके बारे में क्या कोई कदम उठाने जा रही है या मल्टी नेशनल्ज़ को केंटकी फ्राइड चिकन से ले कर पेप्सी के जूस तक आने की इजाज़त दे रही है। (**वयवधान**)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उपसभाध्यष महोदय, जागेश देसाई जी ने जो सवाल उठाया है भोजन की सामग्री और ठंडे पेय, यह ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिये। यह सवाल जो आज यहां उठाया गया है मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर जल्दी ध्यान दे कर इस व्यवस्था को ठीक करवाए।

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि पेप्सी जो दो सौ रुपए किलोग्राम के हिसाब से पोटेटो चिप्स बेचती है वह भी स्टेशनों पर बेचने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। यह सदन नहीं चाहेगा कि दो रुपए किलोग्राम आलू खरीदा जाए और दो सौ रुपए किलोग्राम पोटेटो चिप्स बेची जाए और मुनाफा मल्टी नेशनल कम्पनी बेहिसाब कमाती चली जाए। मैं

बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो यह बात कही जा रही है इस पर पूरी रोक लगनी चाहिए और यह पैसा हिंदुस्तान के किसान को नहीं मिलता है। यह मल्टीनेशनल को मिल रहा है।

श्री मोहम्म सलीम (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, जगेश देसाई जी ने जो सवाल उठाया है पूरे सदन ने इसके साथ एसोसिएट किया है और सभी ने अपनी सहमति दी है। तो हम समझते हैं कि यहां जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद हैं वे जो सदन की भावना है उसे प्रधान मंत्री के पास रखें। वित्त मंत्री तो चले गए हैं। उनको आगे कदम उठाने के लिए कहा गया था कि पीछे कदम उठा गए। लेकिन मैं यह कहता हूं कि पेप्सी को जिस तरह से तवज्जह दी जा रही है, प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है उसे तो कम से कम बंद करें। यह काफी मतलब निलर्ज्जता है।

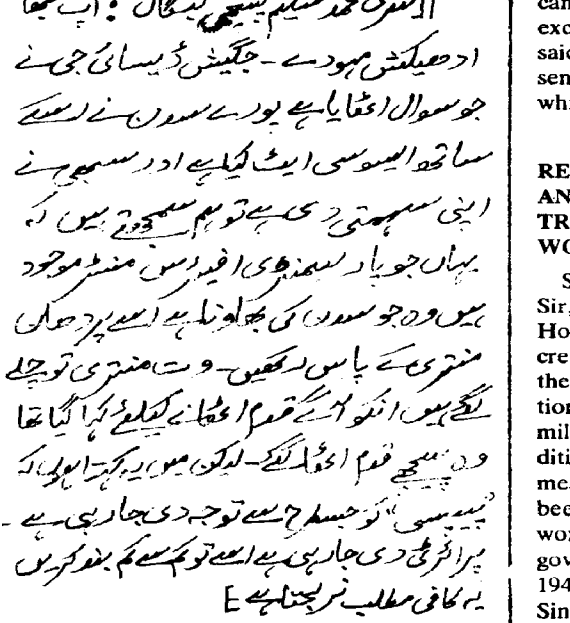

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: महोदय, मारग्रेट आल्वा जी यहां मौजूद है। दिग्विजय जी ने 29 मई को इस प्रश्न को उठाया था और उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि प्रधान मंत्री जी को वे सदन की भावना से अवगत करा देंगी। तो उन्होंने अवगत कराया कि नहीं कराया। दो महीने बीत गए हैं, उनको जरा बताने तो दीजिए। व्हाट इज द रिएक्शन?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, I had said that I would send the proceedings of that day to the Prime Minister...*(Interruptions)*...

THE SATYA PRAKASH MALAVIYA: No, no; you said 'your feelings', not the proceedings.

SHRI DIGVIJAY SINGH: You said 'your feelings'.

SHRIMATI MARGARET ALVA: "Feelings" is the record of the House. I cannot convey them in any other way, except through the record of what was said in the House. I said that I would send the entire proceedings of the day, which was done that very day.

RE: NEED TO IMPROVE WORKING AND LIVING CONDITIONS OF CONTRACTUAL AND CONSTRUCTION WORKERS

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, I wish to draw the attention of the House and the Government to the increasing distress of contract workers and the workers connected with the construction industry whose number is around 20 million, with poor service and living conditions. Whatever social security measures are granted to them have not been implemented. Sir, both the contract workers and the construction workers are governed by the Minimum Wages Act of 1948 so far as their wages are concerned. Since 1948, the Minimum Wages Act has not been revised, has not been changed despite the fact that the Committee of the Labour Ministers made several recommendations in its Report of 1990. The service conditions of Contractor workers are governed by the Contract